BACKGROUNDERS
Press Information Bureau
Government of India

पीएम - एबीएचआईएम

महामारी के लिए तैयार स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचे का निर्माण

24 अक्टूबर 2025

मुख्य बिंदु

- पीएम -एबीएचआईएम ने महामारी की तैयारी और आपातकालीन स्थिति के लिए भारत के स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 64,180 करोड़ (2021-26)राशि आवंटित की
- अक्टूबर 2021 में शुरू किया गया यह **प्राथमिक से तृतीयक स्तर तक स्वास्थ्य सुविधाओं को अपग्रेड करता है** जिसमें देशभर में एएएम, लैब, क्रिटिकल केयर ब्लॉक और निगरानी प्रणाली शामिल हैं।
- मिशन **सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज लक्ष्यों को आगे बढ़ाता है** और एसडीजी-3 लक्ष्यों के साथ संरेखित करता है

प्रस्तावना

कोविड-19 महामारी के दौरान, जन स्वास्थ्य सेवाएँ जैसे परीक्षण, मामले का पता लगाना, निगरानी, प्रकोप प्रबंधन, गंभीर देखभाल की मांग ज्यादा थीं। महामारी ने भविष्य के प्रकोपों, आपात स्थितियों और जन स्वास्थ्य के विकास के लिए प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिक,

माध्यमिक और तृतीयक स्तरों पर भारत की स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने की आवश्यकता को उजागर किया।

25 अक्टूबर, 2021 को शुरू किया गया प्रधान मंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) 2021-26 की अवधि में 64,180 करोड़ रुपये के निवेश के साथ इन स्वास्थ्य संबंधित स्थितियों से निपटने में सहायता करता है । राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में निहित और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन तथा आयुष्मान भारत योजना के साथ एकीकृत, पीएम-एबीएचआईएम प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों को मजबूत करता है, रोग निगरानी प्रणालियों का विस्तार करता है तथा स्वास्थ्य अनुसंधान का समर्थन करता है। आयुष्मान आरोग्य मंदिरों, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं और महत्वपूर्ण देखभाल सुविधाओं के निर्माण के माध्यम से यह योजना भारत के सार्वभौमिक स्वास्थ्य लक्ष्यों को आगे बढ़ाते हुए महामारी संबंधी तैयारी का निर्माण करती है।

मई 2025 में, WHO के सदस्य देशों ने COVID-19 के सन्दर्भ में तीन साल की बातचीत के बाद दुनिया का पहला महामारी समझौता अपनाया। समझौते का उद्देश्य महामारी को रोकने के लिए प्रतिक्रियाओं को अधिक न्यायसंगत बनाना और रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया में वैश्विक समन्वय को मजबूत करना है - टीके, निदान और उपचार विज्ञान तक उचित पहुंच सुनिश्चित करना है।

इस संकल्पपत्र में कार्यों को पूरा करने की दिशा में उठाए गए कदमों की रूपरेखा तैयार करना है, जिसमें एक अंतर सरकारी कार्य समूह (आईजीडब्ल्यूजी) के माध्यम से एक रोगज़नक़ पहुंच और लाभ-साझाकरण (पीएबीएस) प्रणाली स्थापित करने के लिए एक अनुबंध का मसौदा तैयार करना शामिल है। एक बार विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा अपनाए जाने और 60 देशों द्वारा अनुमोदित होने के बाद समझौता लागू हो जाएगा।

सदस्य राज्यों ने IGWG को महामारी की रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए समन्वय वित्तीय तंत्र की स्थापना करने में सक्षम बनाने और महामारी के दौरान स्वास्थ्य उत्पादों तक समय पर और सस्ती पहुंच सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और रसद नेटवर्क (जी एस सी एल) को भी निर्देशित किया। यह समझौता वैश्विक प्रकोप का पता लगाने और प्रतिक्रिया को बढ़ाने के लिए पिछले साल संशोधित अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमों का अनुपालन करता है

नीतिगत ढाँचा

पीएम- एबीएचआईएम राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और आयुष्मान भारत योजना के साथ जुड़कर भारत की स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करता है। यह भारत सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य पहल हैं एवं विशिष्ट कार्यक्रम हैं जो अपने लक्ष्यों से संबंधित और उनका पूरक है।

नीति आधार: राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 सामुदायिक स्वास्थ्य प्रणालियों के महत्व पर ज़ोर देती है, जिसमें स्थानीय स्वशासन और समुदाय-आधारित संगठनों के सहयोग से काम करने वाले प्रशिक्षित प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता शामिल हैं, जो आपदा तैयारी और सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन—जिसे 2005 में शुरू किया गया था—कमजोर आबादी को सुलभ, किफ़ायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने के लिए समुदाय-स्वामित्व वाली और विकेन्द्रीकृत स्वास्थ्य प्रणालियाँ स्थापित करता है। एनएचएम ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, रोग उन्मूलन और स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना सहित कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। मिशन के प्रयास भारत के स्वास्थ्य सुधारों, विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के दौरान, का अभिन्न अंग रहे हैं और देश भर में अधिक सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

यहाँ तक कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने समुदाय-आधारित स्वास्थ्य सेवा वितरण की नींव रखी थी, 2017 की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति ने इन प्राथमिकताओं को सुदृढ़ किया और आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से और अधिक विस्तार के लिए मंच तैयार किया, जिस पर अब पीएम-एबीएचआईएम आधारित है।

आयुष्मान भारत योजना

2018 में शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना दो प्रमुख घटकों के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा वितरण को मजबूत करने के लिए एनएचएम की नींव पर आधारित है:

- **आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम)**
- **पीएम-जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई)**
- **पीएम-एबीएचआईएम**
- **आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन**

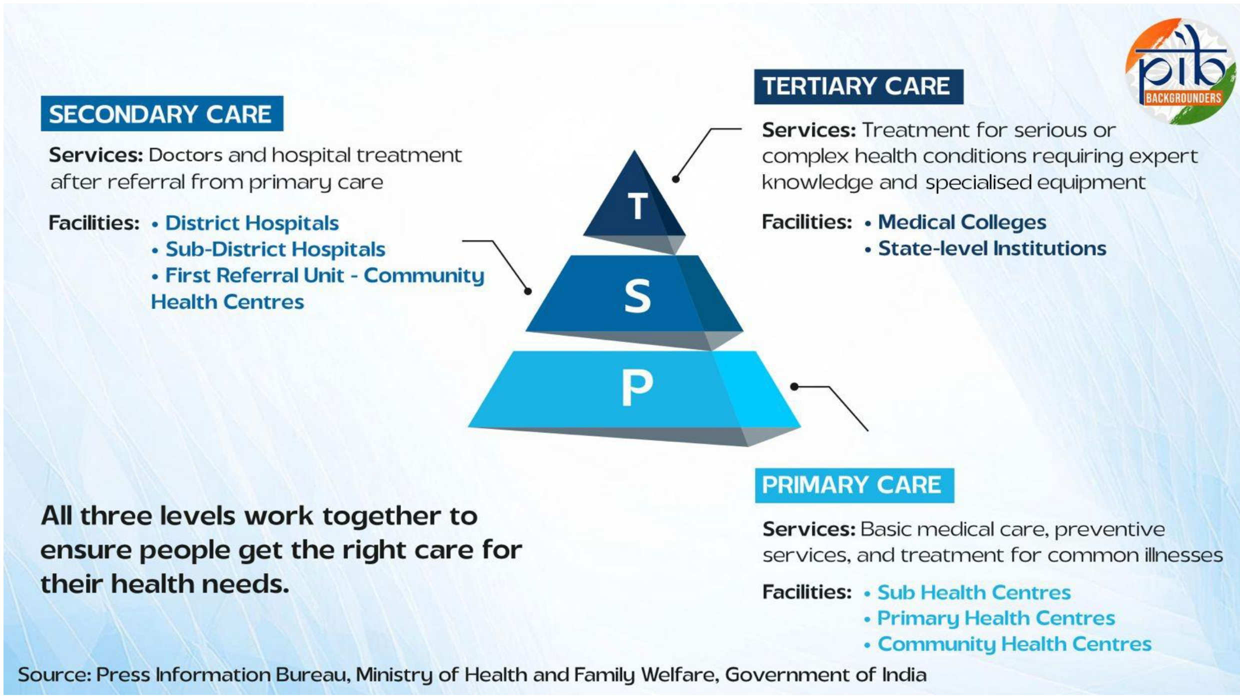

पीएम-एबीएचआईएम का अतिरिक्त मूल्य: बुनियादी ढांचा और क्षमता निर्माण

2021 में शुरू किया गया, प्रधानमंत्री-आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) भारत के सबसे बड़े अखिल-राष्ट्रीय कार्यक्रमों में से एक है, जिसका उद्देश्य एक लचीली, सुलभ और आत्मनिर्भर सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली विकसित करना है।

यह मिशन प्रत्येक जिले में आयुष्मान आरोग्य मंदिरों (एएएम), ब्लॉक सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों, एकीकृत जिला सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं और गहन देखभाल अस्पताल ब्लॉकों की स्थापना और उन्नयन के माध्यम से जमीनी स्तर से जिला स्तर तक स्वास्थ्य अवसंरचना को मजबूत करने पर केंद्रित है। इन सुविधाओं का उद्देश्य सेवा वितरण अंतराल को पाटना और समुदायों के करीब व्यापक प्राथमिक, माध्यमिक और गहन देखभाल सुनिश्चित करना है।

पीएम-एबीएचआईएम एक आईटी-सक्षम, वास्तविक समय रोग निगरानी नेटवर्क का विस्तार करके महामारी और आपदा तैयारियों को भी प्राथमिकता देता है जो प्रकोपों का प्रभावी ढंग से पता लगाने, जांच करने और रोकथाम के लिए ब्लॉक, जिला, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर प्रयोगशालाओं को एकीकृत करता है।

इसके अतिरिक्त, यह वन हेल्थ दृष्टिकोण को आगे बढ़ाकर, विशेष रूप से कोविड-19 और अन्य संक्रामक रोगों पर स्वास्थ्य अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देता है, जो मानव, पशु और पर्यावरणीय स्वास्थ्य की परस्पर निर्भरता को मान्यता देता है।

इस मिशन का उद्देश्य शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में झुग्गी-झोपड़ियों में शहरी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र (एएएम) बनाकर और उप-केंद्रों को एएएम में परिवर्तित करके महत्वपूर्ण कमियों को पूरा करना है।

कुल मिलाकर, पीएम-अभियान एक मजबूत स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र की कल्पना करता है जो भविष्य की स्वास्थ्य आपात स्थितियों का सामना करने में सक्षम हो और साथ ही सभी नागरिकों के लिए समान और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करे।

3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING

2030 तक संचारी रोगों की महामारी को समाप्त करना, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करना और सभी के लिए सुरक्षित और सस्ती दवाओं और टीकों तक पहुंच प्रदान करना सतत विकास लक्ष्य- 3 के कुछ लक्ष्य हैं। भारत सरकार एसडीजी का समर्थन करती है।

पीएम-एबीएचआईएम के प्रमुख उद्देश्य

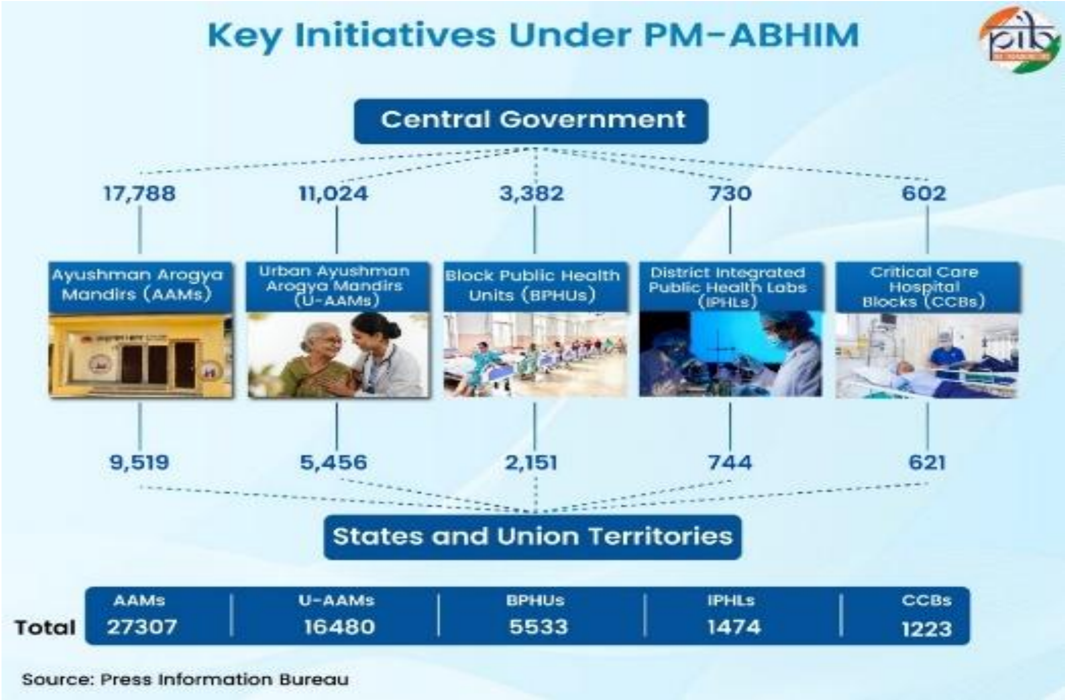

प्रधानमंत्री-आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) ने अपनी केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) घटक के अंतर्गत उल्लेखनीय प्रगति की है, जिसका उद्देश्य वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान सभी स्तरों पर स्वास्थ्य अवसंरचना को सुदृढ़ करना है।

नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, 17,788 भवनविहीन उप-स्वास्थ्य केंद्रों को आयुष्मान आरोग्य मंदिरों (एएएम) में उन्नत करने की स्वीकृति दी गई है, और झुग्गी-झोपड़ियों और वंचित शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा का विस्तार करने के लिए 11,024 शहरी एएएम (यू-एएएम) स्थापित किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, ब्लॉक-स्तरीय स्वास्थ्य प्रशासन और सेवा वितरण को सुदृढ़ करने के लिए 3,382 ब्लॉक जन स्वास्थ्य इकाइयाँ (बीपीएचयू) स्थापित की जा रही हैं, जबकि निदान और निगरानी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए प्रत्येक जिले में एक 730 एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाएँ (आईपीएचएल) विकसित की जा रही हैं। तृतीयक स्वास्थ्य सेवा को सुदृढ़ करने के लिए, पाँच लाख से अधिक जनसंख्या वाले जिलों में 602 क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक (CCB) स्थापित किए जा रहे हैं।

इन पहलों के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कुल मिलाकर ₹32,928.82 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृतियाँ प्रदान की गई हैं, जिनमें 9,519 एएएम, 5,456 यू-एएएम, 2,151 बीपीएचयू, 744 आईपीएचएल और 621 सीसीबी शामिल हैं। ये सभी प्रयास मिलकर देश भर में समय पर और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में सक्षम एक सुदृढ़, विकेन्द्रीकृत और सुलभ सार्वजनिक स्वास्थ्य नेटवर्क के निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम हैं।

संसाधनों का आवंटन

पी एम एबीएचआईएम के तहत संसाधनों के आवंटन का वित्तीय वर्ष-वार विवरण (करोड़ रुपये में) इस प्रकार है:

घटक प्रकार	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	कुल
केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस)						
केंद्रीय हिस्सा	2412.91	3942.80	3361.67	4495.12	7914.89	**22127.39**
राज्य का हिस्सा	1388.16	2276.34	1962.40	2655.64	4522.42	**12804.95**
15वें एफसी शेयर	2026.98	2965.34	4000.04	4743.88	5536.19	**19272.43**
सीएसएस घटकों का उप-योग	5828.04	9184.48	9324.11	11894.64	17973.50	**54204.78**
सीएस घटक	3327.92	1280.61	1691.69	1656.65	1382.89	**9339.78**
कुल योग	**9155.97**	**10465.09**	**11015.80**	**13551.30**	**19356.40**	**63544.56**
योजना का 1% @ एम एंड ई और पीएमसी के साथ						**64180**

निष्कर्ष

पीएम-एबीएचआईएम शुरु होने के चार साल बाद महामारी संबंधी तैयारियों और आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमताओं को मजबूत करने के लिए 64,180 करोड़ रुपये का निवेश करके भारत के

स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को बदल दिया है। प्राथमिक से तृतीयक देखभाल स्तर तक सुविधाओं को उन्नत करके और निगरानी प्रणालियों को बढ़ाकर, इस योजना ने एक अधिक लचीली स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली का निर्माण किया है। जैसे-जैसे भारत सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज और एसडीजी-3 लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ रहा है, पीएम-एबीएचआईएम का समुदाय-केंद्रित दृष्टिकोण-आयुष्मान भारत पहल के साथ एकीकृत और वैश्विक स्वास्थ्य ढांचे के साथ संरेखित-सुनिश्चित करता है कि देश संकट के समय में सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए बेहतर तरीके से तैयार है।

पीके/केसी/एनकेएस/

References

Press Information Bureau:

- https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2037420
- https://www.pib.gov.in/pressreleaseshare.aspx?prid=1576128
- https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2151239
- https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2037420

Ministry of Health and Family Welfare:

- https://mohfw.gov.in/sites/default/files/Operational%20Guideline%20%28CSS%20Component%29_PM-ABHIM.pdf
- https://mohfw.gov.in/sites/default/files/9147562941489753121.pdf
- https://mohfw.gov.in/sites/default/files/02Chapter.pdf
- https://nhm.gov.in/index1.php?lang=1&level=0&linkid=353&lid=444
- https://mohfw.gov.in/sites/default/files/02Chapter.pdf

Others:

- https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2023/09/Goal-3_Fast-Facts.pdf

- https://www.who.int/news/item/20-05-2025-world-health-assembly-adopts-historic-pandemic-agreement-to-make-the-world-more-equitable-and-safer-from-future-pandemics
- https://www.who.int/news/item/19-05-2025-member-states-approve-who-pandemic-agreement-in-world-health-assembly-committee--paving-way-for-its-formal-adoption
- https://www.who.int/health-topics/one-health#tab=tab_1